Item	Unit	Targets	Achievements
2. **Rural Development:**			
Integrated Rural Development Programme			
No. of Families assisted	Lakh Nos.	2.20	2.95
Jawahar Rozgar Yojana			
Mandays of Employment generated	Lakhs	812.43	945.39
3. **Irrigation:**			
(i) Major & Medium Irrigation	Thousand	75.00	45.30
(a) Potential created	Hectares		
(b) Utilisation of created potential	-do-	75.00	79.60
(ii) Minor Irrigation			
(a) Potential created	-do-	115.00	92.00
(b) Utilisation of Created potential	-do-	94.50	119.10
4. **Power:**			
Installed Capacity	M.W.	125.0	125.00
5. **Transport:**			
Rural Roads Villages connected of population:			
1500 and above	Numbers	100	30
1000 and 1500	Numbers	150	25
6. **Health:**			
(i) Sub-centres	Numbers	100	26
(ii) Primary Health Centres	-do-	290	—
(iii) Community Health Centres	-do-	50	1
7. **Water Supply:**			
Rural Water Supply (villages covered)	-do-	5500	5876
8. **Housing & Urban Development:**			
(i) Constitution of House sites	Numbers	30000	37443
(ii) Environmental Improvement of urban slums (Slum Dwellers benefited)	Numbers	76190	91767

संरचनागत समायोजन कार्यक्रम से उत्पन्न बेरोजगारी

3766. **श्री वीरेन जे० शाह:**
डा० जिनेन्द्र कुमार जैन:

क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि विश्व बैंक ने हाल ही में किए गए एक सर्वेक्षण के माध्यम से इस तथ्य को उजागर किया है कि सरकारी संस्थानों के, वर्तमान ढांचों में पारस्परिक तालमेल बैठाने के कार्यक्रम संरचना समायोजन कार्यक्रम के अन्तर्गत आगामी 3 से 5 वर्ष की अवधि में लगभग 4.5 लाख श्रमिकों के बेरोजगार हो जाने की आंशका है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) आने वाले वर्षों में जिन श्रमिकों के बेरोजगार होने की आंशका है क्या सरकार उनके लिए कोई प्रमुख रोजगार योजना तैयार कर रही है?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री और गैर-पारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुख राम): (क) और (ख) सरकार को यथा उल्लिखित विश्व बैंक के ऐसे किसी अध्ययन की जानकारी नहीं है।

(ग) गैर सांविधिक आधार पर गठित राष्ट्रीय नवीकरण निधि में आधुनिकीकरण, प्रौद्योगिकीय उन्नयन, पुनर्गठन, औद्योगिक यूनिटों के पुनरुत्थान या बन्द होने के कारण फालतू हुए श्रमिकों के पुनर्स्थापन के लिए संसाधनों के प्रावधान की परिकल्पना की गई है।

आठवीं पंचवर्षीय योजना के निवेश में कमी

3767. **श्री वीरेन जे० शाह:**
डा० जिनेन्द्र कुमार जैन:

क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान 30 सितम्बर, 1992 के **"दि इकोनोमिक टाइम्स" में "शार्टफाल इन एट्थ प्लान** इन्वेस्टमेंट फीयर्ड, जी०डी०पी० में बी एराउंड थ्री परसेंट" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो निवेश के लिए निर्धारित लक्ष्य

क्या था और सितम्बर, 1992 के अंत तक सरकारी क्षेत्र में कुल कितनी धनराशि निवेश की गयी तथा कम निवेश के कारण देश के आर्थिक विकास पर पड़ने वाले संभावित प्रभाव के प्रति सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री और गैर-पारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुख राम): (क) और (ख) "आठवीं योजना निवेश में गिरावट का डर, जी०डी०पी० लगभग 3 प्रतिशत हो सकता है" के शीर्षक के तहत दिनांक 30 सितम्बर, 1992 में प्रकाशित "इकानामिक टाइम्स" की खबर से सरकार परिचित हैं। 1992-93 के लिए अनुमोदित सार्वजनिक क्षेत्र परिव्यय 80772 करोड़ रुपए का है जो 1991-92 के परिव्यय की अपेक्षा लगभग 13.6 प्रतिशत अधिक है। सितम्बर 1992 के अंत तक सार्वजनिक क्षेत्र में निवेश की सूचना उपलब्ध नहीं है। 1992-93 के दौरान आर्थिक विकास संबंधी निवेश के प्रभाव का मूल्यांकन करना बहुत जल्दबाजी होगी।

ISS Board meeting

3768. SHRI SANGH PRIYA GAUTAM: Will the Minister of PLANNING AND PROGRAMME IMPLEMENTATION be pleased to state:

(a) the number of times the "ISS Board" held its meeting during the last three years;

(b) when the last meeting of the "ISS Board" was held; and

(c) whether "Cadre Review of ISS" was also discussed in the last meeting of the "ISS Board", if so, what was the decision taken thereon and, if not, the reasons for not including the same in the agenda items?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF PLANNING AND PROGRAMME IMPLEMENTATION AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF NON-CONVENTIONAL ENERGY SOURCES (SHRI SUKH RAM): (a) and (b) During the last three years, one meeting of the ISS Board has been held viz. on 24.11.92.

(c) Cadre Review of ISS was discussed in that meeting. It was decided that the matter should be further pursued with the Ministry of Finance.

Reclamation of non-forest land

3769. SHRI BISHAMBHAR NATH PANDE: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Government propose to reclaim non-forest land which needs development at the earliest;

(b) whether Government have already prepared a plan for the development of the non-forest land; and

(c) if so, what are the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT (DEPARTMENT OF WASTELAND DEVELOPMENT) (COL. RAM SINGH): (a) to (c) The reconstituted National Wastelands Development Board (NWDB) under the newly created Department of Wastelands Development has adopted a broad strategy for sustainable development of non-forest wastelands aimed at checking land degradation, putting such lands to sustainable use and increasing biomass production especially of fuelwood and fodder.

The following schemes have been proposed for implementation during the remaining part of the Eighth Five Year Plan:

1. Integrated Wastelands Development Scheme.
2. Investment Promotional Scheme.
3. Technology Development and Extension Scheme.
4. Support to Non-Government Organisations/Voluntary Associations for Wastelands Development.
5. Scheme for Promotional and Critical Support services.
6. Wastelands Development Task Force.